a former international while the SAI nominee is either a former international or an Officer of SAI dealing with the concerned discipline. The National coach is preferably a qualified person with NIS Diploma in Coaching and a creditable sports background.

Drug Detection Test on Athletes

2505. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whethr Government are aware of the fact that a large number of International Athletes has been banned from participating in competition for consuming drugs;

(b) whether Government proposed to issue directives to all the Organisers for conducting drug detection tests;

(c) whether it is a fact that currently the test samples are sent abroad for obtaining results of consumption of drugs by Athletes; and

(d) whether Government propose to create a fully equipped Laboratory under his Ministry for conducting such tests?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) The National Federations and the Coaches attached to National Campers have been informed by SAI about the banned drugs for conduct of random drug tests. Further, they have also been informed about the penalties likely to be imposed should the sportsperson be tested positive. In addition, scientists from the Dope Control Laboratory are sent to the venues of the National Camps to educate the National campers about the ill-effects of drugs on their health. Random samples of national campers are also collected for testing.

(c) No, Sir. The test samples are now tested in the Dope Control Laboratory at J.N. Stadium, New Delhi.

(d) The equipment of the existing laboratory is being upgraded.

SPDA Centre in Arunachal Pradesh

2506. SHRI NYODEK YONGGAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government of Arunachal Pradesh have submitted any scheme for setting up SPDA centres at different places in the state;

(b) if so, when such scheme was submitted and what is the present status of the scheme; and

(c) by when the Central Government's approval will be given for the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS) (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir. Government of Arunachal Pradesh had submitted a scheme for establishment of a SPDA Centre at Jenging.

(b) The scheme for setting up SPDA Centre at Jenging was submitted by the State Government to Sports Authority of India in August, 1989. Since the proposal was incomplete, further clarification was sought from the State Government. However, in the meanwhile in consultation with the State Government a School was adopted in 1993 under the NSTC Scheme.

(c) The approval for the proposal is likely to be given in the current financial year.

चतुर्वेदी पैनल की सिफारिशें

2507. **श्री गोपालसिंह जी॰ सोलंकी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 18 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 3450 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के शिक्षा मंत्रियों ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में) उप-मंत्री (कु० शैलजा): (क) और (ख) 2.3.1994 को आयोजित की गई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में राज्य सरकारों ने यशपाल समिति की सिफारिशों पर मोटे तौर पर अपनी सहमति जताई। इस प्रकार के दृष्टिकोणों पर मतैक्य की पहचान की गई तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई का जो क्रम अपनाया जाना है उसके बारे में उन्हें सुझाव दिया गया। केन्द्र सरकार के सीधे नियंत्रण में जो स्कूल प्रणाली आती है उसमें इसका कार्यान्वयन केन्द्रीय संगठनों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। चूंकि देश के अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं इसलिए इन सिफारिशों का कार्यान्वयन मुख्यत: राज्य सरकारों पर निर्भर है।

पुस्तकों का प्रकाशन

2508. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान भारत में विभिन्न भाषाओं में कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई;

(ख) देश में जनसंख्या के अनुरूप पुस्तकों के प्रकाशन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है; और

(ग) क्या सरकार भारत में प्रकाशन के विकास के लिए सस्ता कागज उपलब्ध कराने और डाक दरों को कम करने पर विचार करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कु० शैलजा): (क) एक विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) निरक्षरता, निर्धनता, पुस्तकालयों की अपर्याप्त संख्या, पुस्तक विक्रेताओं की कम संख्या तथा प्रकाशकों को पर्याप्त निधियों की अनुपलब्धता आदि कई कारणों की वजह से देश में प्रकाशित पुस्तकों की संख्या, जनसंख्या वृद्धि के अनुसार नहीं बढ़ी है।

(ग) चूंकि कागज तथा कागज के वितरण तथा पेपर बोर्ड पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है अतएव पुस्तक प्रकाशन के लिए कम कीमत पर कागज की आपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रकाशित सामग्री के संबंध में वर्तमान डाक दरें काफी कम हैं, इन दरों में और कमी करने से सरकार को और अधिक नुकसान होगा।

विवरण

पुस्तक सपुर्दगी अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता में प्राप्त भाषावार पुस्तकों की संख्या।

भाषा	प्राप्त की गई पुस्तकों की संख्या	
	1992-93	1993-94
असमी	250	263
बंगाली	1489	1588
अंग्रेजी	8119	10895
गुजराती	435	490
हिन्दी	1514	1547
कन्नड़	744	309
कश्मीरी	10	10
मलयालम	631	646
मराठी	849	828
उड़िया	178	148
पंजाबी	402	273
संस्कृत	62	65
सिंधी	20	8
तमिल	2341	1524
तेलुगु	727	806
उर्दू	253	311
अन्य भाषाएं	27	36
जोड़ :	18051	19647

Performance of Navodaya Vidyalayas in Gujarat

2509. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the aims behind establishing the Navodaya Vidyalayas in the States and whether they have succeeded in achieving the aims;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether any committee has been constituted to supervise their work and the way